ऑनलाइन क्लासों का सहारा

स्टूडेंट्स को नंबर अच्छे आए क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में किताबों और नोटबुकों की मदद लेना आसान था। शिक्षकों के मुताबिक इन स्टूडेंट्स से बातचीत या सवाल-जवाब करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उनकी समझ का स्तर वह नहीं है, जो होना चाहिए था।

सुंदर सिंह।

कोरोना महामारी और लॉकडाउन के बावजूद स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई का काम ठप न हो जाए, इसके लिए ऑनलाइन क्लासों का सहारा लिया गया। लेकिन हाल में हुए एक सर्वे ने बताया है कि ऑनलाइन टीचिंग के जरिए कोर्स पूरा करने की रस्मअदायगी भले कर दी गई हो, वास्तव में स्टूडेंट्स तक वह ज्ञान पहुंच नहीं पाया, जो अकादमिक सत्र के दौरान उन तक पहुंचाया जाना था। एजुकेशन टेक्नलॉजी सॉल्यूशन प्रोवाइडर टीम लीज एडटेक के इस सर्वे में 75 विश्वविद्यालयों के 700 से अधिक छात्रों और ऑफिसरों को शामिल किया गया था। सर्वे में 85 फीसदी स्टूडेंट्स ने माना कि जो कुछ उन्हें सीखना था, ऑनलाइन पढ़ाई के जरिए वे बमुश्किल उसका आधा ही सीख पाए। यह बात और है कि क्लास के दौरान और परीक्षा से भी इसका पता नहीं चला। स्टूडेंट्स को नंबर अच्छे आए क्योंकि ऑनलाइन परीक्षा में किताबों और नोटबुकों की मदद लेना आसान था। शिक्षकों के मुताबिक इन स्टूडेंट्स से बातचीत या सवाल-जवाब करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उनकी समझ का स्तर वह नहीं है, जो होना चाहिए था। विश्वविद्यालयों के 88 फीसदी अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस लर्निंग गैप की भरपाई करने में तीन साल से अधिक का वक्त लग सकता है।

वैसे यह समस्या सिर्फ अपने देश तक सीमित नहीं है। चूंकि महामारी और लॉकडाउन के चलते दुनिया भर में पढ़ाई को ऑनलाइन मोड में शिफ्ट करना पड़ा, इसलिए स्वाभाविक ही लर्निंग का यह गैप भी हर जगह देखा जा रहा है। यह जरूर है कि विकसित देशों के मुकाबले भारत में यह ज्यादा है। जहां फ्रांस में यह गैप 9.84 फीसदी, अमेरिका में 13.8 फीसदी, जर्मनी में 25 फीसदी और ब्रिटेन में 21-30 फीसदी होने का अनुमान व्यक्त किया गया है, वहीं भारत में इसे 40-60 फीसदी बताया जा रहा है। अपने देश में इंटरनेट तक पहुंच रखने वाले परिवारों की सीमित संख्या, किसी भी बदलाव को अपनाने के मामले में सरकारी संस्थानों की मंथर गति और अन्य देशों के मुकाबले लॉकडाउन की ज्यादा लंबी अवधि जैसे कारकों को ध्यान में रखें तो लर्निंग गैप का ज्यादा होना चौंकाता नहीं है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि इसके संभावित नुकसानों से हमें किसी तरह की छूट मिल जाएगी। आधी-अधूरी समझ के साथ पास हुए इन स्टूडेंट्स के लिए अगली क्लास का सिलेबस समझना और मुश्किल होगा। यही नहीं, इसी समझ के साथ जब ये जॉब मार्केट में जाएंगे तो हो सकता है पूरे बैच की एक जैसी स्थिति के चलते कॉम्पिटिशन का लेवल ही नीचे आ जाए और इन्हें जॉब भी मिल जाए, लेकिन बाद में उस जॉब से जुड़ी चुनौतियों से निपटना इनके लिए मुश्किल होगा। ऐसे में लर्निंग गैप को भरने का तरीका यही है कि उच्च शिक्षा के महामारी से पहले वाले तौर-तरीके जल्द अपनाए जाएं। जितना संभव हो, पढ़ाई क्लासरूम में हो। इसका रास्ता तेजी से वैक्सिनेशन करके निकाला जा सकता है। हमें याद रखना होगा कि इस मामले में किसी भी तरह की कोताही का देश के भविष्य पर बुरा असर पड़ेगा।

शक्ति

अशोक वोहरा।

धर्म-दर्शन

भक्त को भगवान के नाम के जप से ही शक्ति मिलती है। क्योंकि नाम के भजन के बिना भगवान कहाँ कृपा करते हैं। पर यह बात सबने आसानी से स्वीकार नहीं की तो नारद ने कहा – अपने मत की प्रतिष्ठा के लिए मैं इसे उचित समय पर प्रमाणित करूंगा। इसके कुछ देर बाद राजदरबार स्थगित हो गया। हनुमान उस दिन दरबार में उपस्थित नहीं थे इसलिए हुनमान को इस विवाद के बारे में कुछ नहीं पता था।

दूसरे दिन राजदरबार लगने से पहले नारद ने हनुमान को बुलाया और कहा –हनुमान! राजदरबार में जाने पर तुम श्रीराम तथा उपस्थित ऋषियों को विनय पूर्वक प्रणाम करना। पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। वे भले ही ऋषि का चोला धारण किए है पर वे ब्राह्मण नहीं हैं। क्षत्रियों की पूजा ब्राह्मणों जैसी नहीं होती।

संपादकीय

सफलता की गारंटी नहीं

सबसे बड़ी बात यह कि इसे सफलता की गारंटी भी नहीं माना जा सकता। बीजेपी ने पिछले दिल्ली नगर निकाय के चुनाव में पूर्व में जीते किसी पार्षद को टिकट नहीं दिया। उससे परिणाम बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ हो ऐसा नहीं दिखा। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी इसका असर नहीं हुआ। बीजेपी और कांग्रेस में यह गुणात्मक अंतर जरूर है कि मोदी या शाह मंत्रियों के चयन में निजी निष्ठा के बजाय पार्टी के राजनीतिक भविष्य तथा वैचारिकता को प्राथमिकता देते हैं। इसके बावजूद यह भविष्य की दृष्टि से चिंताजनक है। संसदीय लोकतंत्र में यह तय होता है कि संसद या विधानसभाओं में बहुमत वाला ही नेता होगा लेकिन फिर भी उस नेतृत्व का चेहरा पहले ही जनता के समक्ष आ जाता है। दुनिया भर में पार्टियां प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या चांसलर पद के उम्मीदवार को सामने रखकर ही जनता के बीच जाती हैं। सदनों के अंदर केवल नेता के निर्वाचन की औपचारिकता पूरी होती है। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसी नेता को ऊपर से थोप दिया गया। गुजरात में अगर अगले चुनावों में बहुमत मिल जाता है तो भी दावे से यह नहीं कहा जा सकेगा कि जीत का कारण संपूर्ण मंत्रिमंडल के बदलाव वाला यह प्रयोग रहा।

मोदी द्वारा किसी भी एक राज्य के विधानसभा चुनाव में उसकी जनसंख्या की तुलना में सबसे ज्यादा सभाएं करने, अमित शाह के लंबे समय तक डेरा जमाने तथा पूरी पार्टी की शक्ति झोंकने के बावजूद किसी तरह 99 स्थानों का बहुमत मिल सका।

फिर से जाति की शरण

अवधेश कुमार।।

गुजरात में विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री पद से हटाना और उनकी जगह भूपेंद्र पटेल को बिठाते हुए मंत्रिमंडल में सारे नए चेहरों को लाना ऐसा प्रयोग है जिसकी चर्चा लंबे समय तक होगी। 2017 के प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोदी और शाह को बहुमत के लिए नाकों चने चबाने पड़े थे। मोदी द्वारा किसी भी एक राज्य के विधानसभा चुनाव में उसकी जनसंख्या की तुलना में सबसे ज्यादा सभाएं करने, अमित शाह के लंबे समय तक डेरा जमाने तथा पूरी पार्टी की शक्ति झोंकने के बावजूद किसी तरह 99 स्थानों का बहुमत मिल सका। माना यही गया कि पटेल जाति की नाराजगी बीजेपी को महंगी पड़ी। ऐसे में विजय रूपाणी की जगह भूपेंद्र पटेल को लाने की पहली व्याख्या यही हो सकती है कि यह पटेलों की नाराजगी दूर करने का प्रयास है। मंत्रिमंडल में 7 पटेलों के अलावा 6 अति पिछड़ों, 5 आदिवासियों, 3 क्षत्रियों, 2 ब्राह्मणों और एक-एक दलित तथा जैन को शामिल किया जाना भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश ही माना जाएगा।

ऐसे में यहां यह प्रश्न उठाना आवश्यक है कि नरेंद्र मोदी को क्यों भारी समर्थन मिलता रहा जबकि वह न पटेल जाति से हैं और न गुजरात में उनका बड़ा जातीय जनाधार है? आज भी गुजरात में उनकी लोकप्रियता किसी भी अन्य

नेता से ज्यादा है तो इसका अर्थ यही है कि पटेलों का बड़ा तबका भी उन्हें अपना नेता मानता है। 2014 और 2019 का चुनावी विश्लेषण बताता है कि समाज के एक बड़े वर्ग ने जाति, संप्रदाय और क्षेत्र से ऊपर उठकर मोदी के पक्ष में मतदान किया। ऐसे में स्वयं मोदी चुनावी सफलता के लिए जातीय समीकरण को निर्णय के केंद्र में लाएंगे, इस पर सहसा विश्वास करना मुश्किल है। ऐसा हो तो इसे क्या कहा जाएगा? क्या इसे जाति और संप्रदाय के भेदभाव से ऊपर उठकर मतदान करने वालों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कहेंगे? गुजरात के सीमित संदर्भ में बात करें तो भी पटेलों की नाराजगी आनंदीबेन पटेल के मुख्यमंत्री रहते ही सामने आ गई थी। अगर किसी पटेल का मुख्यमंत्री होना या मंत्रिमंडल में पटेल समुदाय के लोगों का पर्याप्त संख्या में रहना नाराजगी दूर करता तो आनंदीबेन पटेल की जगह विजय रूपाणी को मुख्यमंत्री बनाने की नौबत नहीं आती।

गुजरात में संपूर्ण मंत्रिमंडल के परिवर्तन से जो संदेश निकल रहे हैं वे वर्तमान और भविष्य दोनों लिहाज से नुकसानदेह कहे जा सकते हैं। स्वयं मोदी केंद्रीय मंत्रिमंडल के साथ-साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों के चयन में भी जाति और क्षेत्र से ज्यादा उनकी योग्यता, ईमानदारी और वैचारिक निष्ठा को अहमियत देते रहे हैं। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर का कोई जातीय आधार नहीं रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ संन्यासी हैं। यह भी विचार करने का विषय है कि कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बाद वहां मंत्रिमंडल के चयन में यह कसौटी नहीं अपनाई गई। उत्तराखंड में भी यह कसौटी नहीं थी।

गुजरात प्रयोग के दूसरे पहलू भी चिंता पैदा करते हैं। मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्रियों को जगह नहीं देने का अर्थ तो यही है कि जिसने बेहतर काम कर अपनी योग्यता साबित की और जिसने अच्छा काम नहीं किया, वे दोनों बराबर माने गए। इससे आम धारणा यही बनेगी कि भैया, आप काम करो न करो मोदी जी की जब इच्छा होगी आपको हटाकर किसी और को बिठा देंगे।

वैसे यह बात पहले से साफ थी कि राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक स्तरों पर सरकार और संगठन में व्यापक परिवर्तन होंगे क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान तथा पश्चिम बंगाल पराजय के बाद बीजेपी अपेक्षानुरूप प्रखर भूमिका निभाने में विफल रही है।

अष्टयोग-5055

2		4	5			1
	28	1	36		30	
3			6	7		2
	36	2	37		25	
4	5					3
	33	7	37	4	33	5
1		3	4		6	

प्रस्तुत खेल सुडोकू व जोड़ की पद्धति का मिश्रण है. खड़ी व आड़ी पंक्तियों में 1से 7 तक के अंक लिखने अनिवार्य हैं. गहरे काले वर्ग में लिखी संख्या चारों ओर के 8 वर्गों की संख्या का कुल योग होगी, सीधी अथवा आड़ी पंक्तियों में 1 से 7 तक के अंक होना अनिवार्य है.

अष्टयोग 5054 का हल

4	3	7	5	6	1	2
5	38	3	32	1	27	7
7	4	5	2	3	6	1
3	32	2	32	7	33	6
6	1	4	7	2	5	3
2	24	1	36	4	30	5
1	3	6	7	5	2	4

Jagrutidaur.com, Bangalore

अपना ब्लॉग

नेतृत्व तथा मंत्रिमंडल में परिवर्तन

मोहन। बीजेपी को ध्यान रखना चाहिए कि कांग्रेस इसी शैली में नेतृत्व तथा मंत्रिमंडल में परिवर्तन करती थी। हालांकि वहां भी पूरे मंत्रिमंडल को बदलने की घटना कभी नहीं हुई। इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय तक इससे पार्टी को कोई बड़ा नुकसान होता नहीं दिखा लेकिन अनेक राज्यों में जिस ढंग से पार्टी खत्म होने के कगार पर है उसका एक बड़ा कारण यही है कि केंद्रीय नेतृत्व ने राज्यों में मनमाने परिवर्तन किए। इस समय नरेंद्र मोदी के रूप में केंद्रीय नेतृत्व सशक्त और प्रभावशाली है तो इसके विरुद्ध बड़ा विद्रोह नहीं दिखेगा लेकिन आवश्यक नहीं कि हमेशा इतना ही सक्षम नेतृत्व रहे। इस तरह के निर्णय की परंपरा बनी तो यह भविष्य में पार्टी के विभाजित होने का कारण भी बन सकता है। इनमें आगामी चुनावों का भी ध्यान रखा जाएगा। लेकिन जैसा परिवर्तन गुजरात में हुआ उसे तर्क की कसौटी पर सही साबित करना कठिन है।